भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः155
उत्तर देने की तारीखः 02.03.2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

†***155. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:**
क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का एनईपी कार्यान्वित करने के लिए राज्य-वार कार्य-योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या एनईपी का लक्ष्य देश में और देश के बाहर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए छात्रों को अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल से सुसज्जित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के संबंध में श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 155 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनता की परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस उद्देश्य के लिए, ऑनलाइन, जमीनी स्तर पर और विषयगत विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से एक अत्यधिक भागीदारी, समावेशी और बहु-आयामी परामर्श प्रक्रिया की गई। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 31 मई 2019 को मंत्रालय को प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (डीएनईपी 2019) प्रस्तुत की गई है। प्रारूप एनईपी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf और https://innovate.mygov.in/list-nep/ पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया था। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को डीएनईपी 2019 पर उनके विचार और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के माननीय सांसदों के साथ एक शिक्षा संवाद दिनांक 31.07.2019, 01.08.2019 और 02.08.2019 को लगातार तीन दिन तक आयोजित किया गया था। स्कूल शिक्षा के राज्य शिक्षा सचिवों और उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के राज्य सचिवों के साथ दो बैठकें क्रमशः दिनांक 09.07.2019 और 08.08.2019 को आयोजित की गईं। विभिन्न हितधारकों से प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति परचर्चा करने के लिए केब की एक विशेष बैठक दिनांक 21.09.2019 को आयोजित की गई थी। हितधारकों के बीच व्यापक प्रचार हुआ है और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं है। तदनुसार, प्रारूप एनईपी पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी फीडबैक / टिप्पणियों के आधार पर, मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकारों के सहयोग से नीति में निर्धारित लक्ष्यों को समबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

****